

जिला मजिस्ट्रेट संख्या 166/2022(GCMS : 2022/236) ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स
जिला मजिस्ट्रेट जिला पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज-II, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769,
सावर रोड अन्न सलाई, चैन्नई-600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल
सुन्दर इन्डियन रोड, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम जयपुर-302019 राज. **बनाम**
1. श्री महेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री इन्द्र चंद वर्मा पता 106, सेतिया कॉलोनी, गली नं.
07, वार्ड संख्या 18, जिला श्रीगंगानगर - 335001 2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री महेन्द्र
कुमार वर्मा पता 106, सेतिया कॉलोनी, गली नं. 07, वार्ड संख्या 18, जिला
श्रीगंगानगर - 335001



24.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढा की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार वर्मा एवं सुनीता को ऋण सुविधा के रूप में 13.90/- लाख रुपये (अखरे रुपये तेरह लाख नब्बे हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 05, जी ब्लॉक (क्षेत्रफल 198 वर्गफीट) श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 20.09.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 20.09.2021 को 15,03,055/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 24.09.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। इस बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई अप्रार्थी महेन्द्र

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 05, जी ब्लॉक (क्षेत्रफल 198 वर्गफीट) श्रीगंगानगर
के भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

सं. प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में
उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी
अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण
महेन्द्र कुमार वर्मा एवं सुनीता को 13.90/- लाख रुपये (अखरे रुपये तेरह लाख
नब्बे हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज
में अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार वर्मा ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 05, जी ब्लॉक
(क्षेत्रफल 198 वर्गफीट) श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के
प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार
अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 20.09.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो
गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 24.09.2021 को
जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.09.2021 को भिजवाये गये
है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार वर्मा एवं
सुनीता को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रेक उपलब्ध है
एवं ऑनलाईन ट्रेक पर Item Returned Addressee cannot be located अंकित है, जिसके
अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामिल नहीं हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के
लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला
मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा
13(2) के नोटिस की तामिल ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी
आवश्यक है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार वर्मा को जहां सम्पत्ति प्लॉट नं. 05, जी ब्लॉक (क्षेत्रफल 198 वर्गफीट) श्रीगंगानगर, जो जहाँ बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के सम्बन्धित जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 24.09.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 24.09.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार वर्मा एवं सुनीता को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.09.2021 को भिजवाना अंकित है जिसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार वर्मा एवं सुनीता को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रेक पर Item Returned Addressee cannot be located अंकित है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना नहीं माना जा सकता है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते हैं तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 24.09.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवाया है और अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार वर्मा एवं सुनीता को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन के सम्बन्ध में प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Demand Notice

The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.**

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

चूँकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 24.09.2021 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है और धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण ऋणी/सहऋणी/गारंटर पर नोटिस की तामील स्वयं पर होनी आवश्यक है जबकि अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार वर्मा एवं सुनीता को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT)**

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर

RULE 3(4) के प्रावधानों की अवहेलना है। इस प्रकार समस्त न्यायालयों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।

कोई भी न्यायालय किसी भी प्रचलित/प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं कर सकता है और इसके सम्बन्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versus Arvind Kumar & Anr के पैरा-13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये हैं :

13. In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that generally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see also : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

चूंकि अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार वर्मा एवं सुनीता पर उक्त RULE 3(4) के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) के नोटिस की तामील न होने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशदीप)

जिला माजस्ट्रेट
श्री गंगानगर